



2026:AHC: 2842

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19615 वर्ष 2025

श्रीमती सरोज वर्मा

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:

सर्वेश कुमार पांडेय, शिव कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार सिंह और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विजय लाल को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) के पद पर हुई थी और वह 30.06.2025 को सेवानिवृत्त हो गई, लेकिन उन्हें सेवानिवृत्ति के लाभ नहीं दिए गए हैं, जिनमें 10 महीने के अर्जित अवकाश का नकदीकरण, बड़े हुए महंगाई भत्ते की किस्तों का बकाया, सरकारी/सहकारी बीमा राशि, सामान्य भविष्य निधि, और अन्य सभी लंबित सेवानिवृत्ति लाभ, 18% ब्याज के साथ शामिल हैं।

3. वर्तमान याचिका में प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 5, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला झांसी द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

5. ऐसे सुझाव पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

6. विरोधी पक्षों के तर्कों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ **निस्तारित** किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे; जो इसे प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से याचिकाकर्ता के दावे को तय करने की कार्यवाही करेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 5 की यह राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उसे प्रेषित कर दिए जाएं।

7. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह न निकाला जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किया है।

8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)